(घ) बांदा जिले में सिंचाई के लिये केन नदी से पानी लेने के लिये दो छोटी पम्प नहर योजनायें (जिनमें से एक पहले ही पूर्ण कर ली गई है) और मेसूनी नदी से पानी लेने के लिये एक छोटी पम्प नहर योजना (पहले पूर्ण करली गई है) को कार्यान्वित किया जा रहा है। बंधाई, बाल्मीकि और गन्टा नदियों पर कोई भी उत्थित सिंचाई योजना अनुमोदित नहीं की गई है। किन्तु बंधाई नदी पर एक मध्यम पम्प नहर योजना कार्यान्वित करने के लिये जांच पड़ताल की जा रही है, और इसे राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

२० जिलों में कृषकों के लिये छोटी विकास एजेंसी

4407. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 जिलों के छोटे कृषकों के लिए ऐजेंसियां स्थापित करने के बारे में घोषणा कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर इन एजेंसियों को स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) किन जिलों में इन ऐजेंसियों को स्थापित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) क्षेत्र का चयन प्रारम्भ में सम्भाव्य जीवनक्षम छोटे कृषकों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धि, सहकारी संरचना की शक्ति तथा भूगर्भजल की विद्यमान क्षमता पर निर्भर करता है।

(ग) बिहार में जिला पूर्णिया तथा पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग में दो एजेंसियां स्थापित की गई हैं। मध्य प्रदेश ने छिन्दवाड़ा जिले में ऐसी एजेंसी स्थापित करने का विचार किया है। अन्य राज्यों ने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं बनाये हैं।

Staff Problems in Sindri Fertilizer Factory

4408. SHRI NAMBIA :
SHRI JYOTIRMOY BASU :
SHRI MOHAMMAD ISMAIL:
SHRI BHAGABAN DAS:

Will the Minister of **LABOUR AND REHABILITATION** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the terms of agreement reached between the labour of the Sindri Fertilizer Factory and the Management in 1967 on the basis of the promise given by the former Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals have not yet been implemented;

(b) whether it is also a fact that the State Implementation and Evaluation Committee's recommendations which were made in October, 1968 have also not been implemented ;

(c) whether the question of promotion of the categories like Chargemen, L. D. Cs. etc. is not decided despite the recommendations given by the labour Department of the Bihar Government; and

(d) whether it is a fact that Sindri Unit has not yet got recognised trade union through verification process or otherwise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the House after it is received.